मेक इन इंडिया का पांच साल

लेखक - क्रिस्टोफ जाफरलॉट (किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट, लंदन में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर) तथा विहंग जुमले (फेलो, आइकगाई लॉ, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

17 अक्टूबर, 2019

"श्रम, भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार से पहले विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश विचित्र प्रतीत होता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को इन शब्दों के साथ मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की: "मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ, 'मेक इन इंडिया'। कहीं भी बेचो लेकिन निर्माण यहाँ करो।" मोदी ने भारत का औद्योगीकरण करने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने में चीन का अनुकरण करने की इच्छा जताई, जो एक ऐसा देश है जिसकी यात्रा इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कई बार किया था। आधिकारिक तौर पर, इनका उद्देश्य 2022 तक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12-14 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाना था, जिससे तब तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का निर्माण हो सके।

पाँच साल बाद इस नीति ने विषम परिणाम देने शुरू किए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2013-14 में 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 36 बिलियन डॉलर तो हो गया है, लेकिन इस उल्लेखनीय उपलब्धि को दो दृष्टिकोणों से योग्य नहीं माना जा सकता। पहला, एफडीआई ने 2016 से अपनी स्थिर स्थिति दर्ज कराई है और दूसरा, ये भारत के औद्योगिकीकरण में योगदान नहीं दे रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वास्तव में अवनति पर है।

2017-18 में यह 7 बिलियन डॉलर से ऊपर था जबकि 2014-15 में 9.6 बिलियन डॉलर था। अधिकांश एफडीआई (23.5 बिलियन डॉलर) सेवा क्षेत्र में जाते हैं जो कि विनिर्माण क्षेत्र के तीन गुना से अधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पारंपरिक मजबूत बिंदुओं का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है जहाँ कम्प्यूटर सेवाएँ, उदाहरण के लिए, उल्लेखनीय रूप से विकसित हैं। लेकिन क्या कोई देश औद्योगिक आधार विकसित किए बिना सेवाओं पर भरोसा कर सकता है? इसका जवाब निश्चित रूप से ना है और यही कारण है कि सरकार ने 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू किया था।

उस वक्त का उद्देश्य निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देना था; जहाँ विदेशी निवेशकों को भारत में निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं था कि वे भारत के लिए निर्माण करें। लेकिन भारत के इस विचार से कुछ ही निवेशक आकर्षित हुए और निर्मित उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत ही रही, जहाँ चीन की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत है।

अब सवाल उठता है कि मेक इन इंडिया बेहतर परिणाम देने में नाकाम क्यों रहा? इसका पहला कारण, भारतीय एफडीआई का एक बड़ा हिस्सा न तो विदेशी है और न ही प्रत्यक्ष, यह मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों से आता है। भारतीय कर अधिकारियों को संदेह था कि इनमें से अधिकांश निवेश भारत से 'काला धन' था, जिसे मॉरीशस के माध्यम से भेजा गया था। दूसरा, भारतीय कारखानों की उत्पादकता कम है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत के विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक थाईलैंड और चीन के

अपने समकक्षों की तुलना में औसतन लगभग चार और पाँच गुना कम उत्पादक हैं।'

यह सिर्फ अपर्याप्त कौशल के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि बड़े पैमाने की किफायती अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, आधुनिक उपकरणों में निवेश करने और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों का आकार बहुत छोटा है। अब सवाल उठता है कि कंपनियाँ छोटी क्यों हैं? शायद हमारी पसंद के कारण क्योंकि 100 से अधिक कर्मचारियों वाले संयंत्रों के लिए श्रम नियम अधिक जटिल हैं।

किसी भी कर्मचारी को ले जाने से पहले 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सरकार की मंजूरी आवश्यक है और अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत कर्मचारी के नौकरी विवरण या कर्त्तव्यों में सरल बदलाव के लिए सरकार और कर्मचारी की मंजूरी की आवश्यकता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर भी एक समस्या क्षेत्र है। यद्यपि भारत और चीन में बिजली की लागत लगभग समान है लेकिन बिजली की कटौती भारत में बहुत अधिक है। इसके अलावा, भारत में परिवहन में अधिक समय लगता है। गूगल मैप्स के अनुसार, बीजिंग से शंघाई के बीच 1, 213 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 12.5 घंटे लगते हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के माध्यम से 1, 414 किलोमीटर की दिल्ली से मुंबई की यात्रा में लगभग 22 घंटे लगते हैं।

चीन में औसत गति लगभग 100 किमी प्रति घंटा है जबकि भारत में लगभग 60 किमी प्रति घंटा है। भारत में रेलवे संतृप्त हो गया है जबकि भारतीय बंदरगाह कई एशियाई देशों द्वारा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2016 के विश्व बैंक के वैश्विक प्रदर्शन सूचकांक ने भारत को 160 देशों में 35वें स्थान पर रखा। सिंगापुर को पाँचवाँ, चीन को 25वाँ और मलेशिया को 32वाँ स्थान दिया गया। सिंगापुर में औसत जहाज वापसी का समय एक दिन से भी कम था; भारत में यह 2.04 दिन था।

नौकरशाही की प्रक्रिया और भ्रष्टाचार भारत को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना रहे हैं। इसने विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स में प्रगति की है लेकिन फिर भी 190 देशों में 77वें स्थान पर है। भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 में से 78वें रैंक पर है। उदाहरण के लिए, एक संयंत्र बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना मुश्किल है। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा संकलित नवीनतम वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 10 स्थान फिसल गया है।

श्रम और भूमि अधिग्रहण कानूनों के सुधारों को पूरा करने से पहले मेक इन इंडिया के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास में स्पष्ट रूप से विरोधाभास था। उदारीकरण उन सभी के लिए रामबाण नहीं है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि भारत निर्यात उन्मुख विकास पैटर्न का पालन करना चाहता है तो यह एक शर्त है।

इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम पिछले महीने कंपनी के कर को घटाकर लगभग 35 से 25 प्रतिशत (कम से कम कागज़ पर) रखा गया था जो भारत के अधिकांश पड़ोसियों के साथ तुलनात्मक दर था। यह सुधार विशेष रूप से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के सरकार के प्रयास के अनुरूप है। इस प्रतियोगिता ने अमेरिका-चीन व्यापार विवाद के संदर्भ में एक नया आयाम हासिल किया है।

ट्रम्प प्रशासन द्वारा अमेरिका को चीनी निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के बाद, कई कंपनियाँ अपने संयंत्रों को चीन से अन्य एशियाई देशों में स्थानांतरित कर देंगी। उनमें से कुछ पहले ही ऐसा कर चुके हैं। जापानी वित्तीय फर्म नोमुरा के अनुसार, चीन से स्थानांतरित होने का फैसला करने वाली 56 कंपनियों में से केवल तीन भारत में चली गईं। उनमें से फॉक्सकॉन एक प्रमुख खिलाड़ी है जो अब भारत में अपने टॉप-एंड iPhones का संयोजन करेगा। अन्य बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में विनिर्माण में रुचि दिखाना कब शुरू करेंगी यह देखना अभी बाकी है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. मेक इन इंडिया की शुरूआत 25 सितम्बर 2014 को की गई थी।
   2. इस कार्यक्रम के तहत् विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12 से 14% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना था।
   3. इन कार्यक्रम के द्वारा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?

   (a) 1 और 3

   (b) 1 और 2

   (c) 2 और 3

   (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of Make in India program:-**

   1. Make in India was launched on 25 September 2014.
   2. Under this program, the growth rate of manufacturing sector was to increase from 12 to 14 per annum.
   3. Investment by foreign investors was encouraged through these programs.

   Which of the above statements are incorrect?

   (a) 1 and 3

   (b) 1 and 2

   (c) 2 and 3

   (d) None of the these

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम के पाँच साल पूरे होने पर अगर इसकी सफलता का विश्लेषण किया जाए तो यह अधूरी प्रतीत होगी।' इस कथन के संदर्भ में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख सफलताओं तथा कमियों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

"If the success of the Make in India programme is Analyzed, after completing five years of it, it seems to be half." Analyze the major successes and shortcomings of the Make in India program in the context of this statement.

(250 Words)

नोट : 16 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।